VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS

+918988885050
+918988886060

www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(03 December 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- ताइवान के राष्ट्रपति का अमेरिकी हवाई द्वीप का दौरा
- नये तेल क्षेत्र विधेयक का भारत के पेट्रोलियम उद्योग पर प्रभाव
- मणिपुर में अफीम की अवैध खेती और नृजातीय संघर्ष
- MCQs

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

ताइवान के राष्ट्रपति का अमेरिकी हवाई द्वीप का दौरा:

चर्चा में क्यों है?

- ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते इस साल की शुरुआत में सत्ता संभालने के बाद पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की दो दिवसीय यात्रा पर 30 नवंबर को हवाई पहुंचे। आधिकारिक तौर पर, इस यात्रा को "पारगमन (ट्रांजिट)" के रूप में संदर्भित किया गया है, जो ताइवान पर चीन के दावों को देखते हुए लंबे समय से चली आ रही परंपरा का पालन करता है।
- हालांकि चीन ने इस "पारगमन (ट्रांजिट)" की भी आलोचना की, जो अमेरिका द्वारा ताइवान को लगभग 385 मिलियन डॉलर में F-16 जेट और रडार के लिए स्पेयर पार्ट्स की संभावित बिक्री को मंजूरी देने के एक दिन बाद शुरू हुई।

चीन और ताइवान के वास्तविक चीन के प्रतिस्पर्धी दावे:

- पीपल रिपब्लिक चीन (मेनलैंड चीन) लंबे समय से ताइवान (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चीन) पर अपने क्षेत्रीय दावों को देखते हुए अमेरिका और ताइवान के बीच उच्च-स्तरीय राजनयिक आदान-प्रदान की आलोचना करता रहा है।

- 1949 में पीपल रिपब्लिक चीन के आधुनिक साम्यवादी राज्य की स्थापना के बाद से, इसने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चीन या ताइवान द्वीप पर ऐतिहासिक दावे किए हैं। बदले में, ताइवान ने भी चीन का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा किया।
- शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता के बीच, अमेरिका ने ताइवान का समर्थन किया और आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता दी। हालांकि, 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति और 1978 में आर्थिक उदारीकरण के बाद चीन की बढ़ती वैश्विक ताकत के साथ, अधिक देशों ने मेनलैंड चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। पीपल रिपब्लिक चीन सरकार ने 'वन-चाइना सिद्धांत' को भी अनिवार्य किया, जिसका अर्थ था कि कोई भी देश जो राजनयिक संबंध बनाने की उम्मीद कर रहा है, वह ताइवान की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दे सकता।
- आज, केवल 12 राष्ट्र ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। अधिकांश अन्य देश, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, आदि, मेनलैंड चीन को मान्यता देने के बाद से इसके साथ केवल अनौपचारिक संबंध रखते हैं। परिणामस्वरूप, जब अमेरिका ने 1979 में चीन को मान्यता दी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये, तो उसे ताइवान के साथ अपने संबंधों को कम करना पड़ा।

अमेरिका-ताइवान संबंधों के लिए अंतर्निहित स्थितियां:

- 1972, 1978 और 1982 में चीनी सरकार के साथ संपन्न तीन संयुक्त विज्ञप्तियों में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने "चीनी" स्थिति को "स्वीकार" किया, लेकिन उसका समर्थन नहीं किया कि "केवल एक चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है।" इसने यह भी कहा कि यह "ताइवान के लोगों के साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य अनौपचारिक संबंध बनाए रखेगा"।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के ताइवान के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। यह द्वीप के साथ संबंधों को दूतावास के माध्यम से नहीं बल्कि एक गैर-लाभकारी निगम, अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान (AIT) के माध्यम से संभालता है।

राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की यात्रा की चीन द्वारा आलोचना:

- राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की यात्रा की आलोचना उनकी पार्टी के स्वतंत्रता समर्थक रुख से भी उत्पन्न होती हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 2016 से सत्ता में है और चीन में कम्युनिस्ट सरकार द्वारा इसे "अलगाववादी" कहा जाता है। लाई की पूर्ववर्ती ताइवान की पूर्व राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने 2016 से 2024 के बीच अमेरिका में पारगमन स्टॉप के साथ सात विदेशी यात्राएँ कीं। 2023 में एक यात्रा,

जहाँ उन्होंने हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी और अन्य सदस्यों से मुलाकात की, ने चीन की निंदा की।

- चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनकी पार्टी पर "स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अमेरिकी समर्थन पर अड़े रहने" का आरोप लगाया।
- संभवतः इस यात्रा को धूमधाम से दूर रखने के लिए, जब राष्ट्रपति लाइ होनोलुलु पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए कोई भी उच्च-स्तरीय अमेरिकी या हवाई राज्य अधिकारी नहीं आया। पारगमन के बाद, लाइ मार्शल द्वीप, तुवालु और पलाऊ (ओशिनिया में स्थित) का दौरा करने वाले हैं, जो अभी भी ताइवान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाले कुछ देशों में से हैं।

ताइवान-अमेरिका रक्षा संबंध:

- जुलाई में ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ताइवान को अपनी रक्षा के लिए भुगतान करना चाहिए। ताइवान ने अमेरिका से अरबों डॉलर के रक्षा हथियार खरीदे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तक इस बात का जवाब देने से परहेज किया कि क्या वह चीनी सैन्य कार्रवाई से द्वीप की रक्षा करेंगे।

- उल्लेखनीय है कि "ताइवान संबंध अधिनियम" के तहत अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए बाध्य है, लेकिन इस बात पर रणनीतिक अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है कि अगर चीन द्वारा ताइवान पर आक्रमण किया जाता है तो क्या वह कभी इसमें शामिल होगा।

वर्तमान में अमेरिका-ताइवान सुरक्षा संबंध क्या है?

- संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान को "इंडो-पैसिफिक में एक प्रमुख भागीदार" के रूप में वर्णित करता है। ताइवान की रक्षा करने के लिए नीति के तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि यदि चीन द्वारा ताइवान पर हमला किया जाता है तो क्या वह ताइवान की सीधी रक्षा करेगा, हालांकि राष्ट्रपति जो बिडेन कई मौकों पर कहा है कि वह ऐसा करेंगे।

- उल्लेखनीय है कि अमेरिका इस संबंध में जानबूझकर अस्पष्ट नीति बनाए रखता है - जिसे "रणनीतिक अस्पष्टता" के रूप में जाना जाता है - जो क्षेत्र में अन्य अमेरिकी संधि सहयोगियों, अर्थात्

ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के लिए अपनी स्पष्ट रक्षा प्रतिबद्धताओं के विपरीत है। प्रत्यक्ष अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के बिना, अधिकांश सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि चीन संभावित रूप से काफी लागत पर, बलपूर्वक ताइवान पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा।

- यह भी अज्ञात है कि क्षेत्रीय अमेरिकी सहयोगी देश इस तरह के परिदृश्य में ताइवान की रक्षा करने में किस हद तक मदद करेंगे, हालांकि ताइवान के खिलाफ चीनी आक्रामकता उनके लिए भी गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया दोनों में प्रमुख सैन्य अड्डे रखता है, जो सामूहिक रूप से पचहत्तर हज़ार से अधिक अमेरिकी सैन्य बलों की मेजबानी करते हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

नये तेल क्षेत्र विधेयक का भारत के पेट्रोलियम उद्योग पर प्रभाव:

चर्चा में क्यों है?

- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को राज्यसभा में 2 दिसंबर, 2024 को पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया था, लेकिन बिना किसी विधायी कार्य के राज्यसभा को जल्दी ही दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। यह विधेयक मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था।
- केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य पेट्रोलियम तेल और गैस उत्पादकों के लिए नीति स्थिरता सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की अनुमति देना है। निजी क्षेत्र की कंपनियों को सरकार द्वारा 'शून्य हस्तक्षेप' का वादा करते हुए, यह विधेयक भारत के घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगा और तेल आयात पर निर्भरता को कम करेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

तेल आयात निर्भरता कम करने के लिए, घरेलू उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता:

- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार, पिछली तीन तिमाहियों में भारत का तेल और पेट्रोलियम आयात क्रमशः ₹4,12,178.74 करोड़, ₹4,29,497.96 करोड़ और ₹3,13,029.41 करोड़ रहा है। यह देश के तिमाही तेल और पेट्रोलियम निर्यात का कम से कम तीन गुना है।
- ऐसे में भारत को अपनी तेल आयात निर्भरता कम करने के लिए, पेट्रोलियम के घरेलू उत्पादन में वृद्धि, देश की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग से आगे निकलनी चाहिए।
- उल्लेखनीय है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत उपायों - जैसे कि हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (HELP), खोजे गए छोटे क्षेत्र (DSF) नीति, गैस मूल्य निर्धारण सुधार, और अल्ट्रा-गहरे पानी और उच्च दबाव/उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के लिए कम रॉयल्टी दरें, के बावजूद आयात काफी हद तक अपरिवर्तित रहा है।
- उपर्युक्त संदर्भ में प्रस्तावित संशोधनों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इनका भारत के तेल उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

देश में खनिज तेलों की परिभाषा और इसके पट्टे का विस्तार:

- वर्तमान में, देश में पेट्रोलियम उद्योग पर्यावरण और वन मंजूरी प्राप्त करने में देरी, भूमि अधिग्रहण में जटिलताओं, परिचालन और सुरक्षा अनुपालन के लिए व्यापक मानकों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति से बोझिल है।
- ऐसा माना जाता है कि भारत में अभी तक 13 अरब टन तेल के बराबर की क्षमता है। यह विधेयक भारत को इन संसाधनों का दोहन करने में मदद करने के लिए दो महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है - पेट्रोलियम और खनन गतिविधियों को अलग करना और खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करना।
- उल्लेखनीय है कि तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ही दो ऐसे थे जिन्हें खनिज तेलों के रूप में परिभाषित किया गया था। यह विधेयक परिभाषा का विस्तार करते हुए कोल बेड मीथेन, ऑयल शेल, शेल गैस, शेल ऑयल, टाइट गैस, टाइट ऑयल और गैस हाइड्रेट को शामिल करता है, लेकिन पेट्रोलियम प्रक्रिया में होने वाले कोयला, लिग्नाइट और हीलियम को शामिल नहीं करता है। खनिज तेलों की व्यापक परिभाषा किसी भी नीतिगत भ्रम के बिना पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन संसाधनों की कुशल खोज, विकास और उत्पादन को सक्षम बनाती है।

- इसके बाद, विधेयक पहले से इस्तेमाल किए जा रहे खनन पट्टे में बदलाव करके 'पेट्रोलियम पट्टे' की शुरुआत करता है, जो कंपनियों को खनिज तेलों की खोज, संभावना (तेल और गैस क्षेत्रों की खोज), उत्पादन, व्यापार योग्य बनाने और निपटान करने की अनुमति देता है।

केंद्र की विनियामक शक्तियों का विस्तार:

- इस अधिनियम के तहत, केंद्र को खनिज तेलों के पट्टे, उत्पादन, भंडारण और संरक्षण के अनुदान, नियम और शर्तों, और समय अवधि को विनियमित करने और खनिज तेलों के लिए रॉयल्टी, शुल्क और कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया था।
- यह विधेयक केंद्र की शक्तियों का विस्तार करता है, जिसमें उत्सर्जन को कम करने, तेल उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयों को साझा करने, पट्टों के विलय और पट्टों पर विवादों को हल करने के लिए पट्टेदारों के लिए नियम बनाना शामिल है।
- भारत और ऊर्जा क्षेत्र के हरित प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह विधेयक तेल कंपनियों से हाइड्रोजन उत्पादन, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण या कोयला गैसीकरण जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए तेल क्षेत्रों का उपयोग करने का भी आग्रह करता है।

- इसके अलावा, इस विधेयक में पेट्रोलियम गतिविधियों से संबंधित अपराधों जैसे कि अवैध पट्टे और रॉयल्टी का भुगतान न करना; को भी अपराध मुक्त कर दिया गया है, हालांकि, यह उनके लिए मौद्रिक जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर देता है।
- इस विधेयक में मामूली उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड से प्रशासनिक जुर्माने में बदलाव करके, कंपनियां गंभीर कानूनी परिणामों के डर के बिना अनुपालन और परिचालन सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। इससे अधिक पूर्वानुमानित वातावरण को बढ़ावा मिलेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और नियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

तेल अन्वेषण के लिए निषिद्ध क्षेत्रों को खोलना:

- केंद्र सरकार ने पहले से परिभाषित निषिद्ध क्षेत्रों, जैसे मिसाइल परीक्षण स्थलों के पास, में तेल अन्वेषण की अनुमति दी है। हाल ही में एक बोली में, 1.36 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की पेशकश की जा रही थी, जिसमें से 38% को पहले से निषिद्ध क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा पिछले समय में कार्यान्वयन पर कुछ हद तक सुस्त या धीमी गति से ध्यान केंद्रित करने की भरपाई करने का एक प्रयास है, क्योंकि तेल अन्वेषण और उत्पादन पिछली सरकारों के लिए फोकस में नहीं था।
- जबकि ये सुधार अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, आयात निर्भरता में सार्थक कमी लाने के लिए घरेलू उत्पादन में निरंतर और महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से तेल, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती में।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मणिपुर में अफीम की अवैध खेती और नृजातीय संघर्ष:

चर्चा में क्यों है?

- हाल ही में मणिपुर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (MARSAC) द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 के दौरान मणिपुर में अफीम की खेती में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.13% की कमी आई है, लेकिन अफीम के पौधे की खेती अभी भी राज्य के 16 में से 12 जिलों में बड़े पैमाने पर की जा रही है। सत्ता में आने के एक साल बाद एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में 2018 में "ड्रग्स के खिलाफ युद्ध" की घोषणा की थी।
- उल्लेखनीय है कि 3 मई, 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी-ज़ो लोगों के बीच चल रहे नृजातीय संघर्ष के पीछे पड़ोसी म्यांमार से नशीली दवाओं की तस्करी और पहाड़ियों पर जंगलों को साफ करके बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को कारण माना जा रहा है। इस संघर्ष में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 60,000 अन्य विस्थापित हुए हैं।

अफीम की खेती पर तैयार रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 मार्च, 2022 को राज्य के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक के बाद MARSAC ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके अफीम की खेती वाले क्षेत्रों की वार्षिक निगरानी कर रहा है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 2017 से जनवरी 2024 के बीच 12 जिलों में 19,135.6 एकड़ में अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया।
- अफीम की खेती के खिलाफ अभियान ज्यादातर 2020-21 और 2022-23 में चलाए गए, जिसके दौरान 8,957.1 एकड़ पर फूल वाले पौधों को नष्ट कर दिया गया। नौ जिलों में अफीम की खेती का रकबा 2021-22 में 28,598.91 एकड़ से घटकर 2023-24 में 11,288.1 एकड़ रह गया। ये जिले हैं चंदेल, चुराचांदपुर, कामजोंग, कांगपोकपी, नोनी, सेनापति, तामेंगलोंग, तेंगनौपाल और उखरुल।
- मणिपुर में 2021 से 2023 तक अवैध अफीम की खेती के तहत रकबे में 60.52% की गिरावट आई, जबकि 2022-23 से 2023-24 तक यह गिरावट 32.13% रही।

- मणिपुर सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध का बड़ा असर हुआ है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार बड़े पैमाने पर अफीम की खेती के कारण वनों की कटाई के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, जिसमें मिट्टी का कटाव, जैव विविधता का नुकसान और स्थानीय जलवायु में बदलाव शामिल हैं।

म्यांमार के "अवैध प्रवासियों" द्वारा की जा रही अफीम की खेती की वजह से नृजातीय संघर्ष:

- नवंबर महीने में मणिपुर सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि म्यांमार से आए "अवैध प्रवासियों" द्वारा की जा रही अफीम की खेती की वजह से जातीय संघर्ष चल रहा है। इसमें कहा गया है कि कुकी बहुल जिलों कांगपोकपी, टेंग्नौपाल, चंदेल, चुराचांदपुर और फेरजावल में गांवों की संख्या 731 से बढ़कर 1,624 हो गई है। पांच पहाड़ी जिलों में गांवों की संख्या में असामान्य 122% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिनमें से कई वन क्षेत्रों में हैं, जहां कुकी आबादी काफी रहती है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में पोस्ता (अफीम के पौधे) की खेती एक आकर्षक व्यवसाय रहा है, जिसने गरीब आदिवासी गांवों को इस व्यापार में शामिल किया है, जिन्हें ड्रग माफिया म्यांमार में प्रसंस्करण संयंत्रों की आपूर्ति करने के लिए प्रेरित

करते हैं। मणिपुर के पोस्ता के खेतों से कच्चे उत्पाद को झरझरा अंतरराष्ट्रीय सीमा के माध्यम से म्यांमार में तस्करी कर लाया जाता है, और तैयार उत्पाद - हेरोइन - को उसी मार्ग से भारत में वापस तस्करी कर लाया जाता है।

- मणिपुर सरकार का कहना है कि राज्य में चल रही उथल-पुथल म्यांमार के अवैध प्रवासियों से जुड़ी है, जिनकी वित्तीय जीविका अवैध पोस्त की खेती पर काफी हद तक निर्भर थी, जिसे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के "ड्रग्स पर युद्ध" के तहत महत्वपूर्ण झटके लगे हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQ:

1. हाल ही में चर्चा में रहे 'चीन और ताइवान संबंधों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. मेनलैंड चीन लंबे समय से ताइवान या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चीन और अमेरिका के बीच उच्च-स्तरीय राजनयिक आदान-प्रदान की आलोचना करता रहा है।
   2. ताइवान अपने को चीन का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करता है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

   Ans:(c)

2. विश्व में ताइवान एक प्रमुख सेमीकंडक्टर पावर हाउस है जो लगभग कितने उन्नत सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन के लिए जिम्मेदार है?

   (a) 95 प्रतिशत

   (b) 90 प्रतिशत

   (c) 75 प्रतिशत

   (d) 60 प्रतिशत

   Ans:(b)

3. चर्चा में रहे 'तेल क्षेत्र से जुड़े नए विधेयक का भारत के पेट्रोलियम उद्योग पर प्रभाव' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस विधेयक का उद्देश्य पेट्रोलियम तेल और गैस उत्पादकों के लिए नीति स्थिरता सुनिश्चित करना है।
2. इस नए विधेयक में पेट्रोलियम के साथ-साथ प्राकृतिक गैस को खनिज तेलों के रूप में परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(a)

4. चर्चा में रहे तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) विधेयक; भारत को इसके उपलब्ध पेट्रोलियम संसाधनों का दोहन करने में मदद करने के लिए लाया गया है। भारत में कुल कितने पेट्रोलियम तेल भंडार क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

(a) 52 अरब टन

(b) 33 अरब टन

(c) 28 अरब टन

(d) 13 अरब टन

Ans:(d)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

5. चर्चा में रहे 'मणिपुर सरकार द्वारा अफीम की अवैध खेती के विरुद्ध कार्यवाही' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. MARSAC द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 के दौरान मणिपुर में अफीम की खेती में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 62.13% की कमी आई है।
2. मणिपुर सरकार ने मणिपुर में 2018 से "ड्रग्स के खिलाफ युद्ध" की घोषणा की है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(a)